



हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला में वन सखियों के लिए गैरकाष्ठ वन उपज आधारित आजीविका पर पाँच - दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर रिपोर्ट

Report on Five-Day Training Programme on Non-Timber Forest Produce (NTFP)-Based Livelihoods for Van Sakhis at ICFRE-HFRI, Shimla

भा. वा. अ. शि. प.-हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRDPR), भारत सरकार, हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा संस्थान के सहयोग से हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HPSRLM) की वन सखियों के लिए “गैर-काष्ठ वन उपज (NTFP) आधारित आजीविका पर अनुभवात्मक एवं अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम” का आयोजन 12 से 16 अक्टूबर, 2026 तक किया गया।

इस पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य वन सखियों को गैर-काष्ठ वन उपज (NTFP) एवं लघु वनोपज (MFP) के संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, विपणन तथा इनके माध्यम से आजीविका के अवसरों के संबंध में जानकारी एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना था। साथ ही, प्रतिभागियों को वन संसाधनों के सतत उपयोग तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कौशल से परिचित कराया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. पवन कुमार राणा, प्रभाग प्रमुख, विस्तार एवं वैज्ञानिक-एफ, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला के स्वागत संबोधन से हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा एवं उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की।

संस्थान की निदेशक डॉ. मनीषा थपलियाल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन संबोधन दिया। उन्होंने गैर-काष्ठ वन उपज आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं, के आर्थिक सशक्तीकरण एवं आजीविका संवर्धन की दिशा में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के महत्व पर बल दिया तथा भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दोनों संस्थानों के बीच सहयोग निरंतर जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के उप निदेशक डॉ. ज्योति प्रकाश मोहंती ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से वन सखियों को गैर-काष्ठ वन उपज आधारित आजीविका के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। इससे ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर विकसित करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला के प्रयासों की सराहना की तथा भविष्य में भी दोनों संस्थानों के बीच सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया।

प्रशिक्षण समन्वयक श्री आशुतोष धामी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का परिचय देते हुए इसकी विषयवस्तु एवं गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-काष्ठ वन उपज एवं लघु वनोपज की अवधारणा, संबंधित अधिनियमों एवं नीतियों, वन धन योजना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वन उपज संसाधनों के मानचित्रण तथा मौसमी कैलेंडर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, वन उपज के सतत संग्रहण, संरक्षण एवं पुनर्जनन, सामुदायिक वन प्रबंधन, कानूनी प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छी कृषि एवं संग्रहण पद्धतियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण के दूसरे दिन गैर-काष्ठ वन उपज एवं लघु वनोपज के प्रमाणन, कटाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इन सत्रों में घरेलू एवं निर्यात बाजारों की संभावनाओं, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से उद्यमों के विकास तथा संग्रहण एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया।

प्रशिक्षण के तीसरे दिन विभिन्न योजनाओं के अभिसरण, वन सखियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, सफल उद्यमों के उदाहरणों तथा हिमाचल प्रदेश में गैर-काष्ठ वन उपज आधारित आजीविका की संभावनाओं पर सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वन संसाधनों के प्रभावी उपयोग, वन उपज के मूल्य संवर्धन तथा बाजार से जुड़ाव के विभिन्न अवसरों के बारे में भी जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के चौथे दिन प्रतिभागियों को हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, शिलारू में विकसित अनुसंधान एवं प्रदर्शन गतिविधियों का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को वन संसाधनों के संरक्षण, अनुसंधान आधारित तकनीकों तथा उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों से परिचित होने का अवसर मिला।

प्रशिक्षण के पाँचवें दिन प्रतिभागियों ने संस्थान द्वारा विकसित पॉटरहिल स्थित आर्बोरेटम का भ्रमण किया, जहाँ गैर-काष्ठ वन उपज आधारित स्थलीय प्रदर्शन स्थापित किया गया है। इन शैक्षणिक भ्रमणों के माध्यम से प्रतिभागियों को अनुसंधान आधारित तकनीकों, वन संसाधनों के सतत प्रबंधन तथा आजीविका संवर्धन के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी प्राप्त हुई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान NRLMRC के विशेषज्ञों तथा हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस पहल से वन सखियों की क्षमता निर्माण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन तथा गैर-काष्ठ वन उपज के सतत उपयोग के जरिए ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने में सहायता मिलने की अपेक्षा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला के सहयोग से आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में वन संसाधनों के सतत प्रबंधन, स्थानीय आजीविका संवर्धन तथा ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं, के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

The ICFRE–Himalayan Forest Research Institute, Shimla, in collaboration with the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR), Government of India, Hyderabad, Telangana, organised an **“Exposure cum Orientation Training on Non-Timber Forest Produce (NTFP)-Based Livelihoods”** for the Van Sakhis of the Himachal Pradesh State Rural Livelihoods Mission (HPSRLM) from 12 to 16 October 2026.

The objective of this five-day training programme was to provide the Van Sakhis with information and practical knowledge about the collection, processing, value addition and marketing of Non-Timber Forest Produce (NTFP) and Minor Forest Produce (MFP), along with the livelihood opportunities associated with them. The participants were also introduced to the skills required for the sustainable utilisation of forest resources and strengthening the livelihoods of local communities.

The programme commenced with a welcome address by Dr. Pawan Kumar Rana, Head Extension Division and Scientist-F, HFRI, Shimla. In his address, he briefly outlined the structure and objectives of the training programme.

Dr. Manisha Thapliyal, Director, HFRI, graced the occasion as the Chief Guest and delivered the inaugural address. She appreciated the efforts being made by the National Rural Livelihoods Mission (NRLM) to promote NTFP-based livelihoods. She emphasised the importance of such training programmes in promoting livelihood opportunities and the economic empowerment of rural communities, particularly women. She also stressed the need to continue collaboration between the two institutions for organising similar programmes in the future.

Dr. Jyoti Prakash Mohanty, Deputy Director, National Rural Livelihoods Mission (NRLM), also addressed the participants. Highlighting the objectives of the five-day training programme, he stated that such initiatives would provide the Van Sakhis with comprehensive knowledge of various aspects of NTFP-based livelihoods. This would help develop new livelihood opportunities for rural women and strengthen their economic well-being. He appreciated the efforts of the Himalayan Forest Research Institute, Shimla, in successfully organising the programme and assured continued collaboration between the two institutions in the future.

Shri Ashutosh Dhami, Training Coordinator, introduced the training programme and briefed the participants on its content and activities. He informed them that sessions covered important topics such as the concepts of NTFP and MFP, relevant acts and policies, the Van Dhan Yojana, mapping of locally available forest produce resources, and the preparation of seasonal calendars. In addition, information was provided on the sustainable collection, conservation and regeneration of forest produce, community forest management, compliance with legal provisions, and good agricultural and collection practices.

On the second day of the training, detailed discussions were held on the certification of NTFP and MFP, post-harvest management, processing, value addition and marketing opportunities. The sessions covered important topics, including opportunities in domestic and export markets, enterprise development through Self-Help Groups (SHGs), and the establishment and management of collection and processing units.

On the third day of the training, sessions were organised on the convergence of various schemes, the roles and responsibilities of Van Sakhis, examples of successful enterprises, and the potential for NTFP-based livelihoods in Himachal Pradesh. The participants were also informed about opportunities for the effective utilisation of locally available forest resources, value addition to forest produce, and improved market linkages.

On the fourth day of the training, the participants undertook an educational visit to the research and demonstration activities developed at the Regional Research Centre of the Himalayan Forest Research Institute, Shillaru. The visit provided them with an opportunity to learn about forest resource conservation, research-based technologies, and their practical applications.

On the fifth day of the training, the participants visited the arboretum established by the Institute at Potter Hill, which houses an in-situ demonstration site for NTFP-based resources. These educational visits enabled the participants to gain practical insights into research-based technologies, the sustainable management of forest resources, and approaches to livelihood enhancement.

During the training programme, experts from NRLMRC and scientists and subject specialists from the Himalayan Forest Research Institute imparted training on various topics. The initiative is expected to contribute to the capacity building of Van Sakhis, promote local enterprises through Self-Help Groups, and strengthen rural livelihoods through the sustainable utilisation of Non-Timber Forest Produce.

Organised by the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj under the Ministry of Rural Development, Government of India, in collaboration with the Himalayan Forest Research Institute, Shimla, the training programme represents an important initiative towards promoting the sustainable management of forest resources, enhancing local livelihood opportunities, and strengthening the economic empowerment of rural communities, particularly women, in Himachal Pradesh.

कार्यक्रम की झलकियाँ/Glimpses of the Activity











Media Coverage

वन सखियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू
 शिमला। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला में वन सखियों के लिए गैर-काष्ठ वन उपज आधारित आजीविका पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद के सहयोग से आयोजित यह कार्यक्रम 12 से 16 अक्टूबर तक चलेगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य वन सखियों को गैर-काष्ठ वन उपज एवं लघु वनोपज के सतत संवाहण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के साथ-साथ इनके माध्यम से आजीविका के नए अवसर विकसित करने के लिए व्यावहारिक जानकारी एवं आवश्यक कौशल प्रदान करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के विस्तार प्रमाण प्रमुख एवं वैज्ञानिक डॉ. एमन कुमार राणा के स्वागत संबोधन से हुआ। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। संस्थान की निदेशक एवं कार्यक्रम की मुख्यातिथि डॉ. मनीषा थपलियाल ने अपने उद्घाटन संबोधन में गैर-काष्ठ वन उपज आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने दोनों संस्थानों के बीच भविष्य में भी सहयोग जारी रखने पर बल दिया।

प्रभावों से सामने लाता है। नाटक में सुमा, रोहित गर्ग ने कासी-मनीराम, श्रुति बजंजरी की भूमिकाएं निभाई। खुला रहेगा। (व्यावसायिक गतिविधि)

प्रशिक्षण **औषधीय पौधों की पहचान करने, जंगलों में पाई जाने वाली घास से टोकरियां बनाने का मिलेगा प्रशिक्षण**

जंगलों की उपज से आजीविका कमाने के गुर सीखेंगी वन सखियां

संवाद न्यूज एजेंसी

शिमला। जंगलों से मिलने वाली वन उपज ग्रामीण महिलाओं की आय का साधन बन सकती है। इसके लिए वन सखियों को वन उपज के संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें महिलाओं को औषधीय पौधों की पहचान करने, जंगलों में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की घास से टोकरियां बनाने और अन्य सजावटी वस्तुएं तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला में सोमवार को पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं भाग ले रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद और हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान के सहयोग से 16 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को गैर-काष्ठ वन उपज के माध्यम से आजीविका के अवसरों की जानकारी देना है। प्रशिक्षण के दौरान स्थानीय वन संसाधनों की पहचान, उनके सतत संग्रहण, संरक्षण और प्रसंस्करण की तकनीकें सिखाई जा रही हैं। संस्थान की निदेशक डॉ. मनीषा थपलियाल ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के उपनिदेशक डॉ. ज्योति प्रकाश मोहंती ने कहा कि इससे ग्रामीण महिलाओं को आय बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

शिमला, 12 अक्टूबर (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके लिए स्वरोजगार के नए अवसर विकसित करने के उद्देश्य से हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला में सोमवार को पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के तहत संस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की वन सखियों को गैर-काष्ठ वन उपज आधारित आजीविका के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 16 अक्टूबर तक चलेगा। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य वन सखियों को गैर-काष्ठ वन उपज (एन.टी.एफ.पी.) और लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन की जानकारी देना है।
